

RSWM/SECTT/2025  
September 3, 2025

<p>BSE Limited Corporate Relationship Department, 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, <b>MUMBAI - 400 001.</b></p> <p><b>Scrip Code: 500350</b></p>	<p>National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block - G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), <b>MUMBAI - 400 051.</b></p> <p><b>Scrip Code: RSWM</b></p>
--	--

**Sub: Submission of Newspapers Cutting - 100 days Campaign- “Saksham Niveshak”- for KYC and other related Updations and Shareholder Engagement to Prevent Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividends to Investor Education and Protection Fund (“IEPF”)**

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding 100 days Campaign- “Saksham Niveshak”- for KYC and other related updations and Shareholder Engagement to Prevent Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividends to Investor Education and Protection Fund (“IEPF”) published on 3<sup>rd</sup> September, 2025 in “Business Standard” all edition in English language and in “Business Remedies” & “Nafa Nuksan” Jaipur edition in Hindi language.

The same is also available on the website of the Company at [www.rswm.in](http://www.rswm.in)

Kindly take the same on record. .

Thanking You,

Yours faithfully,  
For **RSWM LIMITED**



**SURENDER GUPTA**  
**SR. VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY**  
**FCS – 2615**  
[rswm.investor@lnjbhilwara.com](mailto:rswm.investor@lnjbhilwara.com)  
Encl.: As above

(Formerly Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited)

**Corporate Office:**  
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1  
Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India  
Tel: +91-120-4390300 (EPABX)  
Fax: +91-120-4277841  
Website: [www.rswm.in](http://www.rswm.in)  
GSTIN: 09AAACR9700M1Z1

**Regd. Office:**  
Kharigram, P. B. No. 28, Post Office Gulabpura - 311 021  
Distt. Bhilwara, (Rajasthan), India  
Tel. : +91-1483-223144 to 223150, 223478  
Fax : +91-1483-223361, 223479  
Website: [www.lnjbhilwara.com](http://www.lnjbhilwara.com)  
GSTIN: 08AAACR9700M1Z3

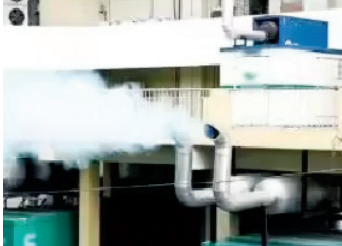
**Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216**

Email: [rswm.investor@lnjbhilwara.com](mailto:rswm.investor@lnjbhilwara.com)



#### For Your Information

### Top 10 Districts by PM2.5 Emissions from Diesel Generator (DG) Sets



- Patna
- Gautam Buddha Nagar (Noida, UP)
- Bengaluru Urban
- Mumbai City
- North 24 Parganas
- Ajmer
- Alwar
- Bhopal
- Thane
- Jodhpur (CSTEP)

Compiled by Nafanuksan Research

#### अमृत वचन



तस्वीर में हर कोई साव्य देते हैं, पर तक्लीक में साव्य देने वाले अपने होते हैं। वरुं होने पर केवल वे ही लोग वाद करते हैं जो मुश्किल परिदृ्यों में काम आते हैं।

- श्री कदम

#### Thoughts of the time

To be ignorant of the lives of the most celebrated men of antiquity is no continue in a state of childhood all our days .

- Plutarch

If your plan "A" doesn't work, the Alphabet has 25 more letters. Say Cool!

- Suresh Rathi

#### राजस्थानी कहावत

**घर में लागीं लाय अर दिसंतरी भद्रा बताय**  
**घर में लगी आग और जौशी कहे भद्रा लगी**

- जब कोई व्यक्ति कारणवश तनिक भी प्रतिक्षा न कर सके, फिर भी प्रतीक्षा के लिए मजबूर होना पड़े, तब।

-स्व. विजय दान देया

साभार : रूपारण सँस्थान, बौलेंडा

### दिल्ली का मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर से तीन गुना अधिक बढ़ा: रिपोर्ट

**नयी दिल्ली@एजेंसी।** दिल्ली के मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024–25 में 11.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय स्तर की 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का करीब तीन गुना है। यह स्थानीय स्तर पर तेज औद्योगिक सुधार का संकेत है।

दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से हाल ही में औद्योगिक उत्पादन पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी का कुल औद्योगिक उत्पादन पिछले वित्त वर्ष में 2023–24 के मुकाबले 9.19 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि चार प्रतिशत रही। यह वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई है और इसमें दिल्ली की 134 मेन्यूफेक्चरिंग इकाइयों एवं एक बिजली इकाई से जुटाए गए उत्पादन आंकड़े शामिल हैं। इन इकाइयों में 90 श्रेणियों के उत्पाद बनाए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में 23 में से नौ मेन्यूफेक्चरिंग इकाइयों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इनमें खाद्य पदार्थ, चमड़ा व संबंधित उत्पाद, मोटर वाहन, परिवहन उपकरण, धातु उत्पाद, रसायन और पेय पदार्थ शामिल हैं।

हालाँकि, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेट्रोलियम, दवाइयाँ और मशीनरी समेत 13 उत्पाद समूहों के उत्पादन में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के कुछ कारखाने पिछले वित्त वर्ष में या तो बंद हो गए या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए जबकि कुछ कारखानों में कोई उत्पादन नहीं हुआ। दिल्ली के बिजली सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024–25 में 3.35 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि दर्ज की जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही।

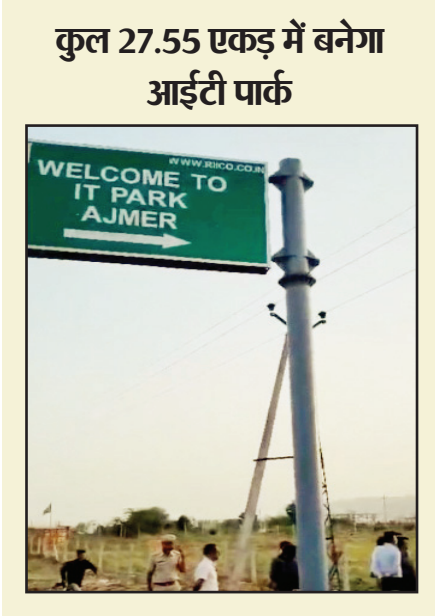
# अजमेर आईटी पार्क के विकास के लिए रीको ने मंजूर किए 23.65 करोड़ रुपये

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

अजमेर में आईटी पार्क की स्थापना के लिए रीको ने 23.65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से भूमि का मुआवजा, समतलीकरण, डिमाकेशन, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन विकास कार्यों की निविदा आमंत्रित कर ली गई है। इन टेंडर्स को 9 सितम्बर को खोला जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के लिए आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बाद से ही आईटी पार्क के विकास के लिए लगातार काम चल रहा है। रीको ने आईटी पार्क के लिए बजट का निर्धारण किया है। रीको के अनुसार आईटी पार्क का कुल क्षेत्रफल 27.55 एकड़ है। इनमें 45 हजार 310 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक और कॉमर्शियल यूज के लिए बेची जाएगी।

उल्लेखनीय है कि रीको ने आईटी पार्क को विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। यहां आईटी कंपनियों के लिए बड़े एवं छोटे आकार के भूखण्ड, होटल, पार्क, पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। आईटी पार्क के लिए राज्य व देश में कार्यरत आईटी कंपनियों से सम्पर्क साधा जा रहा है। रीको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रीको के अधिकारियों से आईटी पार्क की



प्रगति की जानकारी भी ली है। देवनानी ने निर्देश दिए कि आईटी पार्क की भूमि, लेआउट और इसके प्रमोशन का कार्य तेज किया जाए। रीको के अधिकारियों ने बताया कि अजमेर आईटी पार्क को नवाचार और विकास के केंद्र के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यह पार्क आईटी कंपनियों, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जो एक अच्छी तरह से जुड़े और

भविष्य के लिए तैयार कार्यस्थल की तलाश कर रहे हैं। आईटी पार्क में व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध होंगे। प्लॉट का आकार 500 से 3000 वर्गमीटर तक रखा जा रहा है। बड़े आकार के प्लॉट की आवश्यकता हो तो अनुकूलन योग्य स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़े उद्यमों के लिए वह भी उपलब्ध होंगे। यह पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग से सिर्फ एक किमी दूर है। अजमेर शहर के केन्द्र से बहुत कम दूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पुष्कर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है।

यह पार्क सॉफ्टवेयर विकास और आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) से जुड़े व्यवसायों के लिए आदर्श है। इसमें कॉल सेंटर, बीपीओ, मॉडकल ट्रांसक्रिप्शन, कंटेंट क्रिएशन और ई-कॉमर्स समाधान शामिल है। यह डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। इसी तरह हार्डवेयर विनिर्माण और संयोजन को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया यह पार्क कंप्यूटर, बाह्य उपकरणों, नेटवर्किंग उपकरण (राउटर, स्विच, हब), मोबाइल डिवाइस, दूरसंचार प्रणाली, फाइबर ऑप्टिक्स, टचस्क्रीन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों के लिए एा आदर्श है। इससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है।

### फर्जी चंदा, बोगस रिफंड पर आयकर विभाग सख्त

**बीकानेर@नि.सं.** आयकर विभाग, नोखा की ओर से अपर आयकर आयुक्त, रेंज-बीकानेर ललित विश्नोई के निर्देशन में ‘आयकर अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न छूट / कटौतियों की जानकारी’ विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सीबीईओ सहित कुल 68 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता आईटीओ-नोखा ललित कुमार छाबड़ा, आईटीआई (टीडीएस) राम कृष्ण जाखड़ तथा इंस्पेक्टर हनुमान प्रिया जैन थे। मंच संचालन नारायण बच्छ व नवरतन तिवाड़ी ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि आयकर रिटर्न में गलत आय, छूट अथवा कटौती दर्शाने पर पेनल्टी व ब्याज का प्रावधान है। कार्यशाला में राजनीतिक दलों से फर्जी चंदे की रसीद दिखाकर बोगस रिफंड लेने जैसी गड़बड़ियों पर आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली सख्त कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।

## नेशनल • इंटरनेशनल

# जीएसटी 2.0 सुधार, बढ़ती रूरल इनकम और घटती महंगाई से इंडिया की कंजप्शन स्टोरी पकड़ेगी रफ्तार

**मुंबई@आईएनएस।** आगामी जीएसटी 2.0 सुधार, बढ़ती ग्रामीण आय और घटती महंगाई का संयोजन भारत की उपभोग की कहानी में एक बड़े पुनरुत्थान का आधार तैयार कर सकता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। स्मॉलकेस के निवेश प्रबंधक राइट रिसर्च द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का उपभोग चक्र, जो पिछले कुछ वर्षों से सुस्त रहा है, संभवतः अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है और अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर जीएसटी 2.0 को त्योहारी सीजन से ठीक पहले अक्टूबर में अंतिम रूप दिया जाता है, तो इससे उपभोक्ता कीमतें कम हो सकती हैं, मांग बढ़ सकती है और घरेलू खर्च में वृद्धि हो सकती है।

अपेक्षित बदलावों में, जिन वस्तुओं पर वर्तमान में 12% कर लागत है, उन्हें 5% के स्लेब में लाया जा सकता है। इसमें प्रोसेस्ड फूड, किफायती जूते और कुछ स्वास्थ्य उत्पाद शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा है कि इससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती

### डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर मालगाड़ी परिचालन में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

**नयी दिल्ली@एजेंसी।** पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर संयुक्त रूप से मालगार्डियों के परिचालन में 47% की वृद्धि दर्ज की है। इस मार्ग पर 2023 और 2024 के 88,225 के मुकाबले 2024 और 2025 में मालगार्डियों ने 1,30,116 फेरे लगाएं। अधिकारियों ने बताया कि 2024 और 2025 में कुल फेरों में करीब 34% ऐसे फेरे थे जव मालगाड़ी खाली थीं। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर कोयला और सीमेंट के वैगन खाली लौटते हैं क्योंकि इन वैगनों का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए करना संभव नहीं है। 2024 व 2025 में कुल मालगाड़ी परिचालन में कटेनर उत्पादों की हिस्सेदारी 24%, कोयले की 19% और विविध वस्तुओं की 11% थी, जो दोनों गलियारों पर परिवहन की जाने वाली वस्तुओं की सूची में सबसे ऊपर थी। सीमेंट और क्लिंकर (सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल), लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, उर्वरक और पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और स्लैक) जैसी अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी एक से चार प्रतिशत के बीच रही। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीएफसीसीआईएल) ने माल ढुलाई के लिए मालगार्डियों के परिचालन में वृद्धि के लिए अपनी कई पहलों को जिम्मेदार ठहराया है, जिनमें नए माल टर्मिनलों (गति शक्ति कार्गो टर्मिनल) और मार्ग पर ‘साइडिंग’ (मार्ग के किनारे अलग मार्ग) का निर्माण प्रमुख हैं।

हैं और उपभोक्ता बिना ब्रांड वाले उत्पादों से ब्रांडेड उत्पादों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बिग-टिकट आइटम में एयर कंडीशनर और बड़े टेलीविजन जैसे उत्पादों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकता है, जिससे कीमतों में लगभग 8% की कमी आएगी और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में इसकी पहुंच व्यापक होगी। रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी में कटौती खुदरा घरेलू परियोजनाओं और बड़ी निर्माण गतिविधियों, दोनों की लागत कम करेगी, जिस पर वर्तमान में 28% कर लगता है। राइटर रिसर्च की संस्थापक और स्मॉलकेस की निवेश प्रबंधक सोनम श्रीवास्तव ने कहा, जीएसटी 2.0 हाल के वर्षों में सबसे अधिक उपभोग-समर्थक नीतियों में से एक है। रोजमर्रा की श्रेणियों और बिग-टिकट ड्यूरेबल, दोनों में कीमतों में कमी कर, यह सुधार मांग में तेजी ला सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रामीण आय और मुद्रास्फीति के रूझान अनुकूल हो रहे हैं। सेक्टरल आउटलुक भी आशाजनक है। एफएमसीजी

कंपनियों के वित्त वर्ष 26 में 10% की राजस्व वृद्धि देखने की उम्मीद है, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल के क्षेत्र में 21% से अधिक की वृद्धि हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सुधारों को कितनी तेजी से लागू किया जाता है। सीमेंट कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, उनके ईबीआईटीडीए में 40% से अधिक और मुनाफे में 80% की वृद्धि का अनुमान है। एमएसएमई द्वारा डिजिटल समाधानों को अपनाए जाने के कारण इंटरनेट प्लेटफॉर्म के राजस्व में 35-40% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण नकदी प्रवाह में सुधार की उम्मीद है। रिपोर्ट में है कि पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं।

### बैंकएट्सी से गुजर रही सुपरटेक ने पिछले तीन सालों में 6,000 फ्लैट का कब्जा दिया

**नई दिल्ली@एजेंसी।** दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में अपने ग्राहकों को 6,121 फ्लैट का कब्जा दिया है। कंपनी के पूर्व निदेशक आर के अरोड़ा ने यह जानकारी दी। ये फ्लैट कंपनी के पूर्व प्रबंधन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त एक समाधान पेशेवर की देखरेख में 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में दिए।

एनसीएलटी ने 25 मार्च, 2022 के अपने आदेश में सुपरटेक लिमिटेड को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया था। इसके बाद प्रवर्तक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने जून 2022 के अपने आदेश में केवल एक परियोजना इको विलेज-2 के संबंध में कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन का निर्देश दिया था। अन्य सभी परियोजनाएं अंतर्निम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की देखरेख में पूर्व प्रबंधन को पूरी करनी थी।



**आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड**  
**सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216**  
**पंजीकृत कार्यालय:** खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान  
**फोन:** +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479  
**कॉर्पोरेट कार्यालय** : भीलवाड़ा टॉवरस, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा– 201301, (उ.प्र.)  
**फोन:** +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841  
**ईमेल:** [rswm.investor@injbhilwara.com](mailto:rswm.investor@injbhilwara.com); वेबसाइट: <https://www.rswm.in>

**सूचना**  
**(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)**

**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अदस्त/अदावाकृत लाभार्श के हस्तांतरण को रोकने हेतु केवाईसी एवं अन्य संबंधित अद्यतनीकरण तथा शेयरधारक सहभागिता हेतु 100 दिवसीय अभियान – ‘सक्षम निवेशक’**

आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड (**कम्पनी**) के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**एमसीए**) के दिनांक 16 जुलाई, 2025 के पत्र के अनुसारण में, कम्पनी द्वारा 28 जुलाई, 2025 से 6 नवम्बर, 2025 तक चलने वाला 100 दिवसीय अभियान **‘सक्षम निवेशक’** आरम्भ किया गया है। इस अभियान के दौरान, जिन शेयरधारकों ने अपने केवाईसी और नामांकन विवरण अपडेट नहीं किए हैं या जिन्हें बिना दावे वाले लाभार्श और शेयरों से संबंधित कोई समस्या आ रही है, वे कम्पनी या उसके रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (**आरटीए**) एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उनके पते/ईमेल/टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि इस अभियान के अन्तर्गत कम्पनी शेयरधारकों से उनके केवाईसी, बैंक अधिदेश, नामिती एवं संपर्क जानकारी आदि को अद्यतन करने तथा उनके अदस्त/अदावाकृत लाभार्श का दावा करने हेतु संपर्क कर रही है, ताकि उनके शेयरों और लाभार्श राशि को आईईपीएफ में हस्तांतरित होने से रोका जा सके।

किसी भी प्रश्न हेतु कृपया कम्पनी या उसके रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट– एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से निम्नलिखित पते/ईमेल/टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें:

**आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड**  
भीलवाड़ा टावरस, ए–12,  
सेक्टर–1, नोएडा – 201301  
उत्तर प्रदेश

**एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड**  
(यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड)  
179–180, डीएसआईसीसी रोड, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र  
फेज–न, नई दिल्ली–110020, फोन नंबर: 011–41406149–51  
ईमेल आईडी: [helpdeskdelhi@mcsgregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsgregistrars.com)

**कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड**  
**हस्ताक्षर /—**  
**(सुरेंद्र गुप्ता)**  
**वरिष्ठ वी पी लीगल एवं कम्पनी सचिव**  
**एफसीएस – 2615**  
**ईमेल: [rswm.investor@injbhilwara.com](mailto:rswm.investor@injbhilwara.com)**

**स्थान:** नोएडा  
**दिनांक:** 2 सितम्बर, 2025

दिनांक: 3 सितंबर, 2025  
स्थान: जयपुर

विधाना शिक्षण लिमिटेड के लिए  
हस्ताक्षरकर्ता/-  
वासु देव अग्रवाल  
(अध्यक्ष एवं अध्यक्ष निदेशक)  
डीआईएन: 00178146